मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को करौली, हिण्डौन व सपोटरा में अतिवृष्टि के कारण जलभराव प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वे किया।

महाराष्ट्र में हड़ताल पर जायेंगे 18 लाख राज्य कर्मचारी

मुंबई, 13 अगस्त। महाराष्ट्र में 18 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी 29 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने वाले हैं। इसे लेकर राजपत्रित अधिकारी महासंघ की ओर से मंगलवार को राज्य सरकार को नोटिस भेजा गया है। इसमें कहा गया कि राज्य सरकार के 18 लाख 70 हजार अधिकारी, कर्मचारी और शिक्षक 29 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर होंगे। राजपत्रित अधिकारी महासंघ के अध्यक्ष विनोद देसाई ने कहा कि जब तक सरकार अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए संशोधित पेंशन को लेकर नोटिफिकेशन जारी नहीं करती, तब तक हड़ताल जारी रहेगी।

माना जा रहा है कि अगर इतने बड़े पैमाने पर हड़ताल हुई तो राज्य के आम लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसे देखते हुए यह सलाह भी दी जाने लगी है कि सरकारी दफ्तर में कोई काम हो तो उसे जल्द से जल्द निपटा लिया जाए। बता दें कि महाराष्ट्र के सरकारी कर्मचारी

- **महाराष्ट्र के राजपत्रित अधिकारी महासंघ ने 29 अगस्त से हड़ताल पर जाने की घोषणा की।**

यह मांग कर रहे हैं कि उन्हें पुरानी व्यवस्था के हिसाब से पेंशन दी जाए। इसे लेकर सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों ने पिछले साल मार्च में भी हड़ताल की थी, जो 7 दिन तक चली। राज्य सरकार पर इसका असर पड़ा और कर्मचारी व शिक्षक यूनियनों से बातचीत शुरू की गई।

मुख्यमंत्री की ओर से लिखित में यह भरोसा दिया गया कि कर्मचारियों और शिक्षकों को पुरानी पेंशन व्यवस्था के तहत ही आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। मगर, दिसंबर 2023 तक इसे लेकर सरकार की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया। इस पर कर्मचारियों ने 14 दिसंबर, 2023 से फिर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर दी। इसके बाद, कर्मचारी संगठनों के दबाव के चलते सरकार ने अगले बजट सेशन में सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ति वेतन योजना का ऐलान किया था। मगर, सरकार ने अभी तक अपना वादा पूरा नहीं किया।

मु.मंत्री भजनलाल बाणगंगा में डूबे 7 युवकों के घर गए

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंगलवार को बयाना पहुंचे और गत 11 अगस्त को बाणगंगा नदी में डूबकर मरने वाले 7 युवकों के घर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंधाया। मु.मंत्री ने झील का बाड़ा हैलीपैड पर प्रशासनिक अधिकारियों से भी राहत कार्यों की जानकारी ली।

भरतपुर, 13 अगस्त (निसं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को भरतपुर जिले के वर्षा से प्रभावित क्षेत्रों एवं जलभराव व गम्भीर नदी के तटीय क्षेत्रों का हवाई सर्वे किया। उन्होंने झील का बाड़ा हैलीपेड पर प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक लेकर पानी निकासी एवं राहत कार्यों की जानकारी ली।

भरतपुर दौरे में मुख्यमंत्री ने गत 11 अगस्त को बयाना उपखंड के पिदावली गांव के पास बाण गंगा नदी के गड्ढे में डूबे श्रीनगर ग्राम के 7 युवकों के घर गए एवं परिवारजनों को ढांढस बंधाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार दुःख की इस घडी में परिजनों के साथ है। ग्रामीणों ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि दी गई है। परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए और पात्रता के अनुसार अन्य योजनाओं का लाभ दिलाया जायेगा। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार द्वारा दुःख की इस घडी में प्रत्येक परिवार को हर सम्भव सहायता प्रदान कर समस्याओं का निराकरण किया जायेगा।

मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के

- **मुख्यमंत्री ने मृत युवकों के परिजनों को ढाढंस बंधाया तथा हर संभव सहायता देने का आवासन दिया।**
- **मु.मंत्री ने झील का बाड़ा हैलीपैड पर प्रशासनिक अधिकारियों से वार्ता कर राहत व पुनर्वास कार्यों की जानकारी ली।**

झील का बाड़ा स्थित हैलीपेड पहुंचने पर शासन सचिव सहकारिता एवं जिला प्रभारी सचिव शुचि त्यागी, जिला कलेक्टर डॉ. अमित यादव व जिला पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा ने जिले में अत्यधिक वर्षा से प्रभावित क्षेत्रों में बचाव एवं राहत कार्यों की जानकारी दी। इस दौरान बयाना विधायक ऋतु बानावत, वैर विधायक बहादुर सिंह कोली, डीग-कुम्हेर विधायक डॉ. शैलेश सिंह, एडवोकेट मनोज भारद्वाज, स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे।

मु.मंत्री ने करौली-हिंडौन में अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया

करौली, 13 अगस्त (निसं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को करौली जिले के जल भराव क्षेत्र हिण्डौन व सपोटरा क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण कर जल भराव व अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने राजकीय पी.जी. महाविद्यालय करौली में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की व कुशल आपदा प्रबंधन के सम्बंध में आवश्यक निर्देश दिए।

- **मु.मंत्री भजनलाल करौली के राजकीय पी.जी. कॉलेज के प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ली तथा राहत कार्यों के संबंध में निर्देश दिए।**

मुख्यमंत्री ने कहा कि जल भराव से प्रभावित क्षेत्र में पेयजल, खाद्य साम्रगी, दूध, चिकित्सा, आवास सहित अन्य व्यवस्थाओं की समुचित व्यवस्था की जाये। उन्होंने इससे संबंधित सुविधाओं को शीघ्र बहाली करने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने अब तक किये गये राहत एवं पुनर्वास कार्यों की जानकारी ली।

मुख्यमंत्री ने करौली एवं हिण्डौन शहर में जल भराव का स्थाई समाधान करने के लिये भी अधिकारियों को निर्देश दिये।

मुख्यमंत्री ने बताया कि हमारी सरकार जल भराव से प्रभावित लोगों व आमजन को त्वरित एवं प्रभावी सहायता तथा समुचित राहत प्रदान करने के लिए प्रयासरत है। इस दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री, शिखर अग्रवाल, जिला प्रभारी सचिव आशुतोष पेडनेकर, संभागीय आयुक्त सांवरमल वर्मा, भरतपुर के आई.जी. राहुल प्रकाश, जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना, पुलिस अधीक्षक बृजेश उपाध्याय सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक 17 अगस्त को

नई दिल्ली, 13 अगस्त। भाजपा का नया अध्यक्ष कौन होगा? इसे लेकर अभी आलाकमान ने किसी एक नाम पर सहमति नहीं बनाई है। इस बीच देश की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा ने 17 अगस्त को अपने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की एक बैठक बुलाई है, जिसमें पार्टी के सदस्यता अभियान को अंतिम रूप दिया जाएगा।

नए पार्टी अध्यक्ष के चुनाव से पहले यह अभियान पूरा करने का लक्ष्य है। इस बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के अलावा विभिन्न राज्यों में पार्टी संगठन के प्रभारी महासचिव और प्रदेशों के अध्यक्ष भी शामिल होंगे। लंबे समय से चर्चा है कि अध्यक्ष के औपचारिक चुनाव पहले भाजपा एक 'कार्यकारी अध्यक्ष' नियुक्त कर सकती है।

केन्द्रीय सरकार व राज्य सरकार...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

में दी गई हो। उसके बाद रिकवरी प्रक्रिया शुरु कर दी गई थी।

राज्य के मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के हाल के एक फैसे का हवाला देते हुए कहा कि यदि किसी भूमि को वन विभाग की भूमि मान लिया जाता है तो वह हमेशा के लिए वन विभाग की भूमि रहती है। उन्होंने आगे कहा कि पर्यावरण नागरिक अधिकारों से अधिक महत्वपूर्ण होता है। वन विभाग के मंत्री ने अतिरिक्त मुख्य सचिव से कहा कि वह एच.एम.टी. की 559 एकड़ भूमि में से 281 एकड़ भूमि को रिकवर करने के कदम उठाए। सूत्रों ने बताया कि यह कदम पुनरुद्धार योजना को लेकर केन्द्रीय मंत्री के एच.एम.टी. के दौरे के बाद उठाया गया क्योंकि उनके दौरे का उद्देश्य सरकार के प्रयासों पर पानी फेरना था।

कुमारास्वामी ने कहा कि पूरी भूमि एच.एम.टी. की है। उन्होंने इस संबंध में साठ और सत्तर के दशक में पूर्व प्रधानमंत्रियों जवाहर लाल नेहरू और इंदिरागांधी के एच.एम.टी. में किए गए दौरों का उद्धहरण देते हुए कर्नाटक के लिए इसे महत्वपूर्ण बताया। एच.एम.टी. ने वर्ष 1970 में 270 करोड़ का लाभ कमाया था और हैदराबाद, उत्तराखण्ड, अजमेर तथा केरल में भी अपनी शाखाएं खोली थीं।

टाटा के ट्रैक्टर बिज़नैस में आगमन से पहले तक एच.एम. टी. की पिंजोर स्थित ट्रैक्टर मैकिंग यूनिट भारी सफलता प्राप्त कर रही थी। टाटा द्वारा उसके 350 कर्मियों को तोड़ लेने के बाद ही उसका पतन शुरु हुआ।

कुमारास्वामी ने वन मंत्री से प्रश्न किया कि वह इतने वर्षों तक क्यों चुप रहे। उन्होंने एच.एम.टी. की भूमि को रिकवर करने के समय को लेकर उनसे सवाल किया।

केन्द्रीय मंत्री कुमारास्वामी के मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के करीब 40 उपक्रम हैं। उन्होंने दुःख प्रकट करते हुए कहा कि उनमें से करीब 7 बंद होने की कगार पर है तथा वह उन्हें पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं।

कुमारास्वामी ने राज्य सरकार के दावे का विरोध करते हुए कहा कि एच.एम.टी. ने भूमि के बदले धन अदा किया था और राज्य सरकार को भूमि की रिकवरी प्रक्रिया शुरु करने का कोई अधिकार नहीं है।

सिंघानिया ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सुनवाई के दौरान आर.एम.सी. की ओर से कहा कि उन्होंने गलती से याचिकाकर्ताओं से फीस ले ली थी और उन्हें इंटरव्यू के लिए बुला लिया था। इसके लिए आर.एम.सी. ने अदालत में खेद प्रकट कर कहा कि एन.एम.सी. एक्ट के तहत मान्यता लिए बिना एम.बी.बी. एस. कोर्स को मंजूरी नहीं दे सकते। वहीं यूनिवर्सिटी की दलील थी कि ऐसी कई अन्य यूनिवर्सिटी भी हैं, जो बिना मान्यता और कानूनी प्रावधानों के बिना ही कोर्स चला रही हैं।

वहीं याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता सुनील कुमार सिंगोदिया का कहना था कि उन्होंने नीट के जरिए ही यूनिवर्सिटी में प्रवेश लिया था और वे मेडिकल कोर्स करने के पात्र भी थे। उनकी ओर से प्रवेश लेने में कोई दुर्भावना व अनियमितताएं नहीं की गई हैं।

वहीं 18-20 साल के छात्र-छात्राओं से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि उन्हें यूनिवर्सिटियों से जुड़े तकनीकी व कानूनी प्रावधानों की भी जानकारी हो। ऐसे में उनकी एम.बी.बी. एस. की डिग्री को वैध करार देते हुए आर.एम.सी. में उनका रजिस्ट्रेशन करवाया जाए। अदालत ने सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद फैसला बाद में सुनाया जाना तय किया है।

'बहिन सुप्रिया के खिलाफ पत्नी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जाना उल्लेखनीय था।

उपमुख्यमंत्री ने ये टिप्पणियाँ अपनी "जन सम्मान यात्रा" के दौरान कीं। उनकी इस यात्रा का उद्देश्य विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं खास तौर से, "मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना" (एम.एम.एल.बी.वाई.) को प्रचारित प्रसारित करना है। इस योजना के अन्तर्गत, राज्य सरकार की योजना राज्य की सभी महिलाओं को 1500 रु. की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करने की है। यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जायेगी।

समाचार एजेंसी पी.टी.आई. के अनुसार, जब अजित पवार से पूछा गया कि वे अगले सप्ताह आ रहे रक्षाबन्धन के त्योहार पर अपनी चचेरी बहिन सुप्रिया सुले के पास जायेंगे अथवा नहीं, तो उन्होंने कहा कि इस समय वे दौरे पर है तथा अगर उस दिन वे और उनकी बहिनें एक ही जगह हुये, तो वे त्योहार पर उनसे निश्चित रुप से मिलेंगे।

उपमुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उन्होंने तय किया है कि इस यात्रा के दौरान वे उनकी आलोचनाओं पर प्रतिक्रिया देने के बजाय, केवल किसानों, महिलाओं तथा युवाओं के लिये लाई गई विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं के बारे में ही बातचीत करेंगे।

अजित पवार ने यह भी कहा कि शरद पवार वरिष्ठ नेता हैं तथा "पूरे परिवार के मुखिया" हैं तथा वे अपने चाचा द्वारा की गई किसी भी आलोचना पर प्रतिक्रिया नहीं देंगे।

यह पूछे जाने पर कि क्या सीनियर पवार पर सत्तारुढ़ भाजपा तथा शिवसेना निशाना साध रही हैं, एन.सी.पी. नेता ने कहा कि "महायुति" के घटक दलों को यह बात समझनी चाहिये कि वे क्या बोल रहे हैं। उन्होंने कहा, "जब हम साथ-साथ बैठते हैं, तब मैं अपनी राय व्यक्त करता हूँ।"

पिछले वर्ष जुलाई में, अजित पवार, बहुत से अन्य विधायकों के साथ, शिवसेना- भाजपा सरकार में शामिल हो गये थे। अजित पवार के इस कदम के फलस्वरुप, शरद पवार द्वारा स्थापित नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (एन.सी.पी.) टूट गई थी। बाद में, चुनाव आयोग ने अजित के नेतृत्व वाले गुट को "असली" एन.सी.पी. घोषित कर दिया था।

सत्तारुढ़ गठबन्धन 'महायुति' के घटक दलों में गम्भीर मतभेद पहले से चल रहे हैं क्योंकि भाजपा का एक वर्ग पूरी तरह ऐसा मानता है कि अजित पवार को गठबन्धन में लाना एक बहुत बड़ी गलती थी।

उपमुख्यमंत्री के अपनी गलती के स्वीकरण से सत्तारुढ़ गठबन्धन की एकजुटता निश्चित रुप से प्रभावित होगी। शिवसेना (शिन्दे) के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि आगामी सप्ताहों में राज्य की राजनीति में हलचल पैदा होने की संभावना है।

'सिविक वॉलन्टियर स्कीम' क्या है...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अस्पताल में एक सिविक वॉलंटियर कार्यकर्ता द्वारा नृशंस प्रहार और बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई। सिविक वॉलन्टियर्स की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा "पैरा पुलिस फोर्स" के रूप में की जाती है। ये किसी भी पुलिस संगठन के कर्मचारी नहीं होते बल्कि इनका काम कुछ संस्थाओं में औपचारिक पुलिस फोर्स की सहायता करना होता है।

- **ममता बनर्जी सरकार द्वारा जिस लापरवाही से प्रदेश के आम नागरिकों व अब तो मैडिकल स्टूडैन्ट्स की सुरक्षा से खिलवाड़ किया गया है, उससे काफी बेचैनी फैली है तथा हाई कोर्ट ने मामले इस प्रकरण का स्वतः संज्ञान लेकर मामले की जाँच सी.बी.आई. को सौंपने का आदेश दिया है।**

सिविक वॉलन्टियर्स राज्य के मूलतः एक ऐसी राजनीतिक नियुक्ति है जिनमें युवकों को प्रतिमाह एकमुश्त 12,000 रूपए दिए जाते हैं, हालांकि अधिकांश मामलों में ये सिविक वॉलन्टियर्स स्वयं को पुलिस फोर्स का अंग बताकर असामाजिक हो जाते हैं।

इनमें से एक सिविक वॉलन्टियर आर.जी. कार मेडिकल कॉलेज तथा अस्पताल में मनमाने तरीके से घूमता-फिरता रहता था। उसका आना-जाना अस्पताल के इनर वार्ड्स तथा पेशेन्ट्स-ज़ोन्स में भी था। ज्ञातव्य है कि इन स्थानों तक केवल अधिकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर तथा पैरा-मेडिकल ही जा सकते हैं।

सन्दर्भित मेडिकल स्टुडेन्ट ने लगातार 36 घंटे की ड्यूटी की थी तथा एक खाली कॉन्फ्रेन्स रुम में सोने के लिये चली गई थी। सन्दर्भित सिविक वॉलन्टियर उस कमरे में पहुँच गया, वहाँ उसने उस मेडिकल स्टुडेन्ट के साथ दुष्कर्म किया और फिर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद हुई पोस्ट-मॉर्टम रिपोर्ट बताती है कि उस पर क्रूरता से प्रहार किये गये, जिससे उस छात्र की गर्दन एवं हड्डियाँ टूट गईं।

इस दिल दहला देने वाली घटना से हमारा ध्यान राज्य में जवाबदेही तथा सुरक्षा के अभाव पर केन्द्रित हो जाता है। सन्दर्भित अपराधी इससे पहले अस्पताल में घूमता था तथा वहाँ लोगों को धमकाता था। अपने गले में सोने की मोटी चेन पहने वाला यह सन्दर्भित व्यक्ति अपने वस्त्रों पर कोलकाता पुलिस के राजकीय चिन्ह तथा बैच लगाये हुये होता था।

सिविक वॉलन्टियरों की नियुक्ति तथा हाल ही में इनके बारे में हुये अनुभव दर्शाते हैं कि इन लोगों का चयन और नियुक्ति कितने गैर जिम्मेदाराना तरीके से हुई हैं।

चयन और नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया अनियमितताओं तथा मनमानीपूर्ण है। लेकिन सरकार अपनी बात पर अड़ी हुई है तथा वास्तविकता को देखने से इनकार कर रही है।

सबसे बुरी बात यह है कि पुलिस मंत्री स्वयं मुख्यमंत्री ही हैं तथा इस समय पुलिस प्रशासन जिस तरह से चलाया जा रहा है, उसमें किसी प्रकार की कोई जवाबदेही नहीं है।

मेडिकोज़ तथा जनसामान्य की न्यूनतम सुरक्षा के ऐसे उल्लंघन, एवं उसकी ऐसी विफलता के बाद भी, पुलिस मंत्री उदासीन एवं भावविहीन बनी हुई हैं।

बांग्लादेश हिंसा...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

14,586.86 डॉलर पर पहुँच गया था।

2012-13 के बजट में शामिल किये गये इस प्रोजैक्ट का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने तथा बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना ने गत वर्ष नवम्बर में किया था। इन वर्षों में प्रोजैक्ट की लागत जो 2013-14 में 557 करोड़ रूपए थी, से बढ़कर 2015-16 में 887 करोड़ रूपए तथा अन्त में 972.52 करोड़ रूपए हो गई थी। भारत की तरफ वाले काम की फंडिंग मिनिस्ट्री ऑफ डवलपमैंट ऑफ द नॉर्थ-ईस्टर्न रीज़न ने की थी, जबकि बांग्लादेश के हिस्से की राशि भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा दी गई थी।

जयपुर ग्रामीण ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

में कांग्रेस प्रत्याशी रहे अनिल चोपड़ा को भाजपा के राव राजेन्द्र सिंह ने 1615 वोटों के अंतर से पराजित किया था।

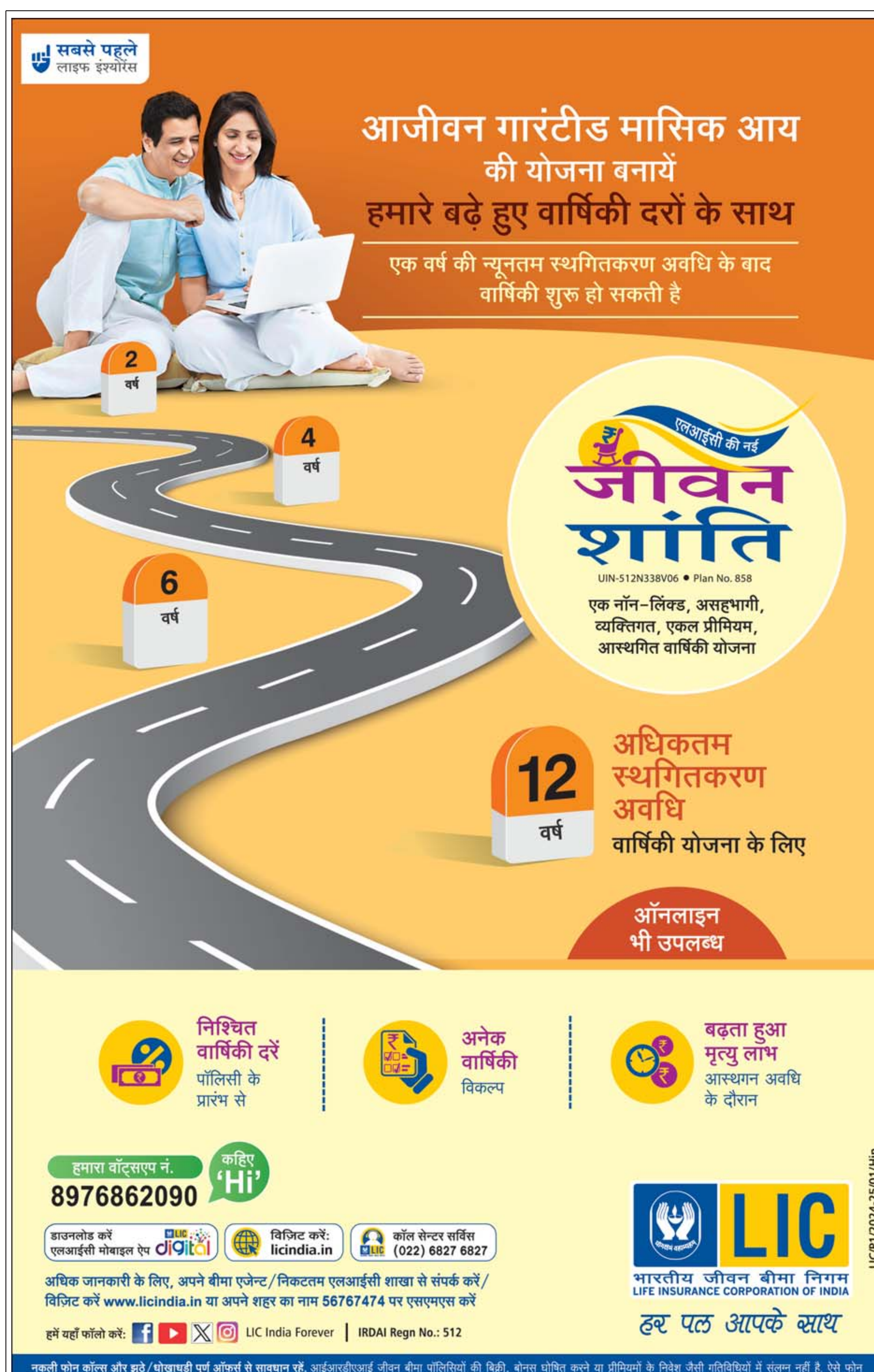

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा मैसर्स अरावली प्रिन्टर्स, राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर (राजस्थान) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 65015/96, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34 फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908